पश्चिम बंगाल में सुवेन्दु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले बंगाल की जनता को दंडवत प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी .

योगी मंत्रिमंडल का आज होगा विस्तार

भूपेंद्र चौधरी, पूजा पाल, मनोज पांडेय बन सकते हैं मंत्री

लखनऊ, 09 मई. उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आज बड़ा राजनीतिक संदेश देने की तैयारी में है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मंत्रिमंडल विस्तार आज करेंगे. शनिवार शाम मुख्यमंत्री ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में हलचल और तेज हो गयी.

इस मंत्रिमंडल विस्तार में पांच से छह नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है. साथ ही कुछ मौजूदा मंत्रियों को हटाए जाने की भी संभावना जतायी जा रही है. भाजपा इस विस्तार के जरिए आगामी चुनावों से पहले सामाजिक और राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश में है. समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा का समर्थन करने वाले विधायक मनोज पांडे और पूजा पाल के मंत्री बनने की चर्चा सबसे ज्यादा है. भाजपा इन दोनों नेताओं को शामिल कर विपक्ष को बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहती है. इसके अलावा नाई समाज से एमएलसी रामचंद्र प्रधान और विश्वकर्मा समाज से वाराणसी के एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है. जाट समाज से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का नाम भी प्रमुख दावेदारों में शामिल है. वहीं ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा और भाजपा प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला के नामों पर चर्चा चल रही है. दलित प्रतिनिधित्व को मजबूत करने के लिए कृष्णा पासवान को भी मौका मिल सकता है. भाजपा इस विस्तार के जरिए प्रदेश के अलग-अलग जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है. खासकर पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल और दलित वोट बैंक पर पार्टी की नजर बनी हुई है. फिलहाल योगी सरकार में मुख्यमंत्री समेत कुल 54 मंत्री हैं और संवैधानिक सीमा के अनुसार अभी कुछ और मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है. ऐसे में रविवार का संभावित मंत्रिमंडल विस्तार यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है. भाजपा संगठन और सरकार दोनों इस विस्तार को आगामी राजनीतिक रणनीति के लिहाज से बेहद अहम मान रहे हैं.

पश्चिम बंगाल में मोदी गारंटी का मेगा ब्लूप्रिंट तैयार

आयुष्मान भारत, पीएम आवास, जल जीवन मिशन और पीएम किसान समेत सात बड़ी योजनाओं को बंगाल में तेजी से लागू करने की तैयारी

कोलकाता 09 मई . पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद अब केंद्र की महत्वाकांक्षी योजनाओं को तेजी से लागू करने का रास्ता खुलता नजर आ रहा है. नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सात बड़े योजनागत कार्यक्रमों पर काम शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है. भाजपा इसे 'मोदी की गारंटी' का विस्तार बता रही है, जिसका उद्देश्य राज्य के हर वर्ग तक सीधा लाभ पहुंचाना है.

सरकार की प्राथमिक सूची में आयुष्मान भारत योजना सबसे ऊपर मानी जा रही है. इसके जरिए गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी है. भाजपा नेताओं का दावा है कि बंगाल के लाखों परिवारों को इसका सीधा फायदा मिलेगा. इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए मकानों के निर्माण को गति देने की योजना बन रही है. जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने पर भी जोर दिया जा रहा है. राज्य सरकार का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट खत्म करने के लिए केंद्र के सहयोग से बड़े स्तर पर पाइपलाइन और जलापूर्ति परियोजनाएं शुरू की जाएंगी. वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना को भी व्यापक स्तर पर लागू करने की तैयारी है ताकि किसानों को सीधे आर्थिक सहायता मिल सके. महिलाओं के लिए स्वरोजगार और आर्थिक सहायता योजनाओं पर भी चर्चा तेज है. स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाने और महिलाओं के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने की योजना पर विचार हो रहा है. बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास और नई भर्ती प्रक्रियाओं को भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल किया गया है. सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और अन्य लंबित मांगों पर भी जल्द फैसले की उम्मीद जताई जा रही है. भाजपा नेताओं का कहना है कि नई सरकार डबल इंजन मॉडल के जरिए विकास की रफ्तार तेज करेगी और केंद्र तथा राज्य के बीच समन्वय से परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जाएगा. राजनीतिक जानकार मानते हैं कि भाजपा बंगाल में विकास और कल्याणकारी योजनाओं को अपने सबसे बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में पेश करना चाहती है. आने वाले महीनों में इन योजनाओं का असर राज्य की राजनीति और जनता दोनों पर साफ दिखाई दे सकता है.

वर्ष 2021 में जबममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस सरकार बनी थी, तब मुस्लिम समाज को मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी दी गयी थी. उस समय फिरहाद हकीम, मो गुलाम रब्बानी, जावेद अहमद खान और मौलाना सिद्दीकुल्ला चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था. इसके अलावा अखरुज्जमान और सबीना यासमीन समेत अन्य नेताओं को राज्यमंत्री का पद मिला था. नई सरकार का यह कदम भाजपा की बदली हुई राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है.

पार्टी अब महिला, अनुसूचित जाति, आदिवासी और मतुआ वोट बैंक पर अधिक फोकस करती दिख रही है. वहीं विपक्ष इसे मुस्लिम समुदाय की अनदेखी बताते हुए सरकार को घेरने की तैयारी में है. तृणमूल कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बंगाल हमेशा सामाजिक और धार्मिक समावेशिता की राजनीति के लिए जाना जाता रहा है. ऐसे में मंत्रिमंडल में मुस्लिम प्रतिनिधित्व का पूरी तरह खत्म होना राज्य की परंपरा से अलग माना जा रहा है. हालांकि भाजपा नेताओं का कहना है कि उनकी सरकार जाति और धर्म नहीं, बल्कि विकास और प्रशासनिक क्षमता के आधार पर काम करेगी.

शेख हसीना ने सुवेंदु अधिकारी को दी बधाई

पश्चिम बंगाल चुनाव में शनिवार को भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण किया . इस मौके पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना ने उन्हें बधाई दी . उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और भारत के बीच सच्ची दोस्ती के इतिहास में पश्चिम बंगाल की एक खास जगह है . बांग्लादेश अवामी लीग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना की तरफ से सुवेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई और शुभकामनाएं . मैं अपनी और बांग्लादेश की जनता की तरफ से सुवेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत और भारत के पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनने पर दिल से बधाई और शुभकामनाएं देती हूं . उन्होंने कहा, 'पश्चिम बंगाल के लोगों का फैसला सुवेंदु अधिकारी की मजबूत और लोगों को ध्यान में रखकर काम करने वाले नेतृत्व के लिए उनके गहरे भरोसे और सारहान को साफ दिखाता है। बांग्लादेश और भारत के बीच सच्ची दोस्ती के इतिहास में पश्चिम बंगाल की एक खास जगह है . हम एक जैसी भाषा, संस्कृति और विरासत से जुड़ा एक संबंध साझा करते हैं और मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में यह संबंध भविष्य में नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा .

बंगाल सरकार में पहली बार मुस्लिम मंत्री नहीं

पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के साथ ही मंत्रिमंडल की संरचना राजनीतिक चर्चा का बड़ा विषय बन गयी है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और पांच अन्य विधायकों ने शनिवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में शपथ ली. लेकिन इस मंत्रिमंडल की सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि इसमें किसी भी मुस्लिम नेता को जगह नहीं मिली. राज्य के इतिहास में यह पहला मौका बताया जा रहा है, जब बंगाल सरकार में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है. नई सरकार ने महिला, आदिवासी और मतुआ समुदाय के नेताओं को प्रतिनिधित्व देकर सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश की है, लेकिन मुस्लिम समुदाय की अनुपस्थिति ने विपक्ष को सरकार पर सवाल उठाने का मौका दे दिया है.

यूपी के संभल से निकला सुवेंदु के पीए मर्डर का कनेक्शन

पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के करीबी और पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में जांच का दायरा अब उत्तर प्रदेश तक फैल गया है. चुनाव परिणाम आने के बाद हुई इस हत्या ने पहले ही बंगाल की राजनीति में सनसनी फैला दी थी, और अब यूपी कनेक्शन सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया है. बंगाल पुलिस को इनपुट मिला था कि हत्या में शामिल आरोपी उत्तर प्रदेश के संभल जिले में छिपे हुए हैं. इसके बाद एक विशेष टीम तत्काल यूपी रवाना हुई. हालांकि जांच के दौरान पुलिस से बड़ी चूक हो गयी. टीम को संभल पहुंचना था, लेकिन गलत सूचना और लोकेशन भ्रम के चलते वह बदायूं पहुंच गयी. बदायूं पहुंचने के बाद बंगाल पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ कई इलाकों में जांच और तलाशी अभियान चलाया. घंटों की कार्रवाई के बावजूद कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा. बाद में यह स्पष्ट हुआ कि टीम गलत पते पर पहुंच गयी थी. इसके बाद पुलिस संभल भी पहुंची, लेकिन वहां भी आरोपियों का कोई पता नहीं चल सका. जांच एजेंसियों का मानना है कि आरोपी लगातार लोकेशन बदल रहे हैं और उन्हें स्थानीय स्तर पर मदद मिल रही हो सकती है. इसी वजह से पुलिस तकनीकी सर्विलांस और मोबाइल लोकेशन के जरिए आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. चंद्रनाथ रथ की हत्या उस समय हुई थी जब पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के बाद राज्य में राजनीतिक तनाव चरम पर था. उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी, जिसके बाद भाजपा ने इसे राजनीतिक साजिश बताया था. पार्टी नेताओं ने राज्य सरकार और प्रशासन पर भी सवाल उठाए थे. अब यूपी तक पहुंची जांच ने इस मामले को और संवेदनशील बना दिया है. पुलिस अधिकारी फिलहाल पूरे नेटवर्क की जांच कर रहे हैं.

और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आरोपी किन लोगों के संपर्क में हैं. भाजपा लगातार निष्पक्ष जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही है, जबकि पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा .

अरोरा की कंपनी ने जारी किया आधिकारिक बयान

नई दिल्ली, 09 मई . ईडी की कार्यवाही से जुड़े हालिया घटनाक्रमों के संदर्भ में हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (कंपनी) निम्नलिखित तथ्यात्मक स्थिति को स्पष्ट करना चाहती है . कंपनी को अपने स्थापित तथ्यों, देश के कानूनी व संवैधानिक ढांचे और माननीय न्यायपालिका के विवेक पर पूरा भरोसा है . भारत सरकार ने मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात को प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में चुना है .भारत का मोबाइल फोन निर्यात कारोबार वित्त वर्ष 2014-15 के लगभग 1,500 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 2 लाख करोड़ रुपए हो गया है .यानी इसमें 127 गुना की भारी बढ़ोतरी हुई है .भारतीय मोबाइल फोन निर्यात के लिए यूएई दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है .इसी राष्ट्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने मई 2023 में मोबाइल फोन निर्यात व्यवसाय में कदम रखा .निर्यात की प्रामाणिकता - कई स्तरों पर स्वतंत्र जांच- निर्यात अवधि के दौरान, कंपनी ने 44,471 ब्रांडेड हैंडसेट और एक्सेसरीज का निर्यात किया, जिनमें एप्पल के आईफोन और एयरपॉड्स (96.7 फीसद), सैमसंग हैंडसेट (3.2 फीसद) और वनप्लस हैंडसेट (0.06 फीसद) शामिल थे - जो सभी टॉप ग्लोबल कंपनियों के ओरिजिनल प्रोडक्ट थे . झआईएम ईआई - असलियत साबित करने वाली खास पहचान- दुनिया में कहीं भी बनने वाले हर मोबाइल फोन का 15 अंकों का एक खास इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर होता है .

▶ कंपनी ने 44,471 ब्रांडेड हैंडसेट और एक्सेसरीज का निर्यात किया

बिना मान्यता धार्मिक संस्थानों पर सुको सख्त

नई दिल्ली, 09 मई. सुप्रीम कोर्ट 11 मई को एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है, जिसमें देशभर में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा या धार्मिक शिक्षा देने वाले सभी संस्थानों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और निगरानी की मांग की गयी है.

इस मामले की सुनवाई शीर्ष अदालत की दो जजों की बेंच करेगी. याचिका में कहा गया है कि देश के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में ऐसे धार्मिक शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिनके पास आधिकारिक मान्यता नहीं है. इन संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी सुविधाओं को लेकर गंभीर सवाल उठाये गये हैं. याचिकाकर्ता का तर्क है कि जब किसी संस्थान में नाबालिग बच्चों को शिक्षा दी जाती है, तो उसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक और प्रशासनिक मानकों का पालन अनिवार्य होना चाहिए.

पश्चिम रेलवे-रतलाम मंडल
ई-निविदा सूचना
वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर, कर्षण वितरण, रतलाम मंडल, पश्चिम रेलवे भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु IREPS पोर्टल के माध्यम से खुली निविदाएं आमंत्रित करते हैं: **निविदा क्रमांक: EL/TRD/58/2026-27/05. कार्य का नाम:** TRD Work in connection with provision of FOBS with ramp at Ujjain under Simhastha 2028. **अनुमानित लागत: ₹ 51,62,342/- बयाना राशि: ₹ 1,03,300/- समापन अवधि: 12 Months. निविदा दस्तावेज़ की राशि:** Nil. **ऑनलाइन बिडिंग बंद होनेकी दिनांक एवं समय:** 01.06.2026 at 15:00 hrs. **ऑफर की वैधता:** 60 days from the date of opening. **वेबसाइट: www.ireps.gov.in नोटिस बोर्ड: वरिष्ठ मंडल विद्युत् इंजीनियर, कर्षण वितरण, रतलाम मंडल, पश्चिम रेलवे के कार्यालय के प्रवेश द्वार के सामने.** CRY/IND/42
हमें लाइक करें : facebook.com/WesternRly

कार्यालय, निमाड़ क्लब समिति, खंडवा
सिविल लाईन्स, खण्डवा, पिन कोड 450001
पत्र क्रमांक / 13 निमाडक्लब / 26 खंडवा दिनांक: 5/5/2026
विज्ञप्ति
पोर्टल टेण्डर क्रमांक 2026_RES_505290_1 निमाड़ क्लब समिति खण्डवा के Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट का 10 वर्ष के लिए PPP मोड पर संचालन एवं संधारण, मासिक किराया आधार पर करने के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी चयन हेतु निविदा

क्र.	ई-टेण्डर पोर्टल क्रमांक	संपत्ति का उपयोग	क्षेत्रफल	न्यूनतम मासिक किराया	EMD राशि (Earnest Money Deposit)
1		Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट का संचालन एवं रखरखाव	कुल 15400 sqf (Banquet hall, कैफे, जिम, 6400 sqf) (क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट 9000 sqf)	75,000/- (पचहत्तर हजार)	5,00,000/- (पांच लाख)

निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी म.प्र. शासन की वेबसाइट (पोर्टल) www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध है। **(डॉ. नागार्जुन बी गौड़ा) (IAS)**
सचिव, निमाड़ क्लब खण्डवा एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, खण्डवा

मुरादाबाद मदरसे पर चला योगी सरकार का बुलडोजर

हाईकोर्ट के आदेश के बाद मदरसे पर बड़ी कार्रवाई

मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, 09 मई. उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माणों के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच मुरादाबाद में शनिवार को बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गयी. मझोला क्षेत्र स्थित मदरसा जामिया अरबिया हयातूल उलूम पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण एमडीएए ने बुलडोजर चलाया. यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद की गयी, जिसके तहत प्रशासन ने पहले विवादित जमीन को अपने कब्जे में लिया था. सुबह से ही प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंच गयी थी. इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया ताकि कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे. इसके बाद पांच बुलडोजरों की मदद से मदरसे के अवैध निर्माण को हटाने का अभियान शुरू हुआ. कार्रवाई के दौरान आसपास के इलाके में लोगों की भीड़ जमा रही. और पूरे क्षेत्र में हलचल का माहौल बना रहा. प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, मदरसे की जमीन और निर्माण को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था.

पश्चिम रेलवे-रतलाम मंडल
शुद्धिपत्र
कृपया निविदा सूचना संख्या Snt_RTM_W_26_Tele_04 के शुद्धिपत्र को प्रकाशित करने की व्यवस्था करें। निविदा सूचना में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं। **मद:** कार्य पूर्ण करने की अवधि. **पूर्व में:** 12 माह. **बदलाव:** 18 माह. शेष **निविदा सूचना** के सभी नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी। CRY/IND/38
हमें लाइक करें : facebook.com/WesternRly

FOR SALE
इंदोर के रेसकोर्स रोड पे एमएनसी कंपनी के स्वामित्व कि ऑफिस 2 कार पार्किंग के साथ बेचने के लिये उपलब्ध है | इच्छुक खरीददार कृपया संपर्क करे
8329436086

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, मल्हारगंज क्षेत्र इन्दौर, म.प्र.
(कोर्ट रूम नं. 104-105 प्रथम तल संयुक्त तहसील कार्यालय, सुपर कोरिडोर पर रेल्वे ब्रिज के पास टिगरिया बादशाह जिला इंदौर)
क्रमांक/233/प्रावाचक/2026 इन्दौर, दिनांक 07/05/2026
विज्ञप्ति
एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक **श्री सचिन व्यास पिता श्री लक्ष्मीनारायण व्यास निवासी- ग्राम कुमेडी तह. जिला इंदौर म.प्र.** द्वारा पुजारी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र मय दस्तावेजों के साथ ग्राम कुमेडी स्थित राम मंदिर, हनुमान मंदिर, भोलेनाथ मंदिरों पर पुजारी के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में जिस किसी भी संस्था व व्यक्ति कोई आपत्ति हो तो नियत **पेशी दिनांक 15/05/2026** के पूर्व प्रस्तुत कर सकता है बाद मियाद प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। **आज दिनांक 07/05/2026** को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
मल्हारगंज क्षेत्र, इंदौर

कार्यालय- अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी सावेर, जिला- इन्दौर (म.प्र.)
क्रमांक- 566/ भू-अर्जन// री-1/2026, सांवेर, दिनांक 17/04/2026
प्ररूप- ख प्र. क्र.- /B-129/2026-27
[नियम-5 का उपनियम (2)]

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सांवेर माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन (एम.एस. पाईप) पाईपलाईन बिछाने के कार्य हेतु ग्राम :- मुण्डला हुसैन, प.ह.नं. 42, रा.नि.मं. - 02, धरमपुरी, तहसील - सांवेर, जिला- इन्दौर (म.प्र.) मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-08, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए। और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है। कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)	कालम नम्बर-5 में उल्लेखित क्षेत्रफल के अतिरिक्त उपयोग हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)	कुल उपयोग किये जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
1	2	3	4	5	6	7
इन्दौर	सांवेर	ग्राम :- मुण्डला हुसैन, प.ह.नं. 42	308/4	0.132	0.437	0.569
			309/3/2			
			309/3/1			
			310/3			
			310/2			
		योग	05	0.132	0.437	0.569

(राकेश मोहन त्रिपाठी),
अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
व सक्षम प्राधिकारी सांवेर, जिला- इन्दौर (म.प्र.)
G12594/26

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
उज्जैन, मध्य प्रदेश में आवासीय एवं कार्यालय उपयोग के लिए जगह की आवश्यकता
बीपीसीएल को अपने प्रोजेक्ट के लिए उज्जैन नगर निगम सीमा के भीतर रहने और ऑफिस के उपयोग हेतु उपयुक्त जगह की आवश्यकता है। इसके लिए इच्छुक लोगों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। जगह का न्यूनतम कार्पेट एरिया 2500 वर्ग फुट (232.3 वर्ग मीटर) होना चाहिए, जिसमें कम से कम दो मास्टर बेडरूम, एक गेस्ट रूम, हॉल और किचन होना जरूरी है। प्रॉपर्टी मल्टीस्टोरी बिल्डिंग, बंगला, विला या फ्लैट हो सकती है। लीज की अवधि टेंडर मिलने की तारीख से 2 वर्ष की होगी, जिसे आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रॉपर्टी में बिजली और पावर बैकअप, पानी की सुविधा, दो कारों के लिए पर्याप्त पार्किंग और नजदीकी हाईवे से अच्छी कनेक्टिविटी होना जरूरी है। नई बनी हुई या अच्छी स्थिति में रखी गई प्रॉपर्टी को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि तुरंत उपयोग किया जा सके। इच्छुक व्यक्ति अपने प्रस्ताव दो सीलबंद लिफाफों (एनवलप -1 और एनवलप -2) में भरे हुए फॉर्म अ और फॉर्म इ के साथ जमा कर सकते हैं।
एनवलप -1 में स्वामित्व दस्तावेज, नवीनतम बिजली बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रसीद, भवन का स्वीकृत नक्शा, पानी का बिल, प्रॉपर्टी की कुछ तस्वीरें, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फॉर्म अ शामिल होना चाहिए।
एनवलप -2 में फॉर्म इ (प्रस्तावित प्रॉपर्टी/क्षेत्र का मासिक किराया) शामिल होना चाहिए।
सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूर्ण प्रस्ताव डाक या व्यक्तिगत रूप से नीचे दिए गए पते पर 30.05.2026 को दोपहर 3:00 बजे तक जमा किए जा सकते हैं।
मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वीबीपीएल, चैप्स इस्टेट, 1st फ्लोर, तारा टावर के पास, करमसद वी वी नगर रोड, आनंद - 388325, गुजरात
बिड दस्तावेज प्राप्त करने के लिए संपर्क करें:
ईमेल आईडी - patidarpraveen@bharatpetroleum.in
मोबाइल - 9928005434